सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट की

मुख्य

विशेषताएं

2023-2024

फरवरी, 2023

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

अमृत काल के लिए विज़न

1. युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर
2. रोजगार सृजन में वृद्धि
3. सुदृढ़ और स्थिर वृहत - आर्थिक वातावरण

सप्तर्षि - 7 प्राथमिकताएं

- समावेशी विकास
- अंतिम छोर तक पहुंचना

- अवसंरचना और निवेश
- युवा शक्ति

अमृत काल

- क्षमता उभारना
- वित्तीय क्षेत्र

- हरित विकास

कृषि और सहकारिताएं

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण

किसानों के लिए सुलभ समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान

कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए

एएनबी* बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम

उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए

लक्षित निधियन

पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्रक को □20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आबंटन

भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना: *'श्री -अन्न'*

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईएमआर^, हैदराबाद को सहायता दिया जाना

व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना

उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाएगा

कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण में वृद्धि

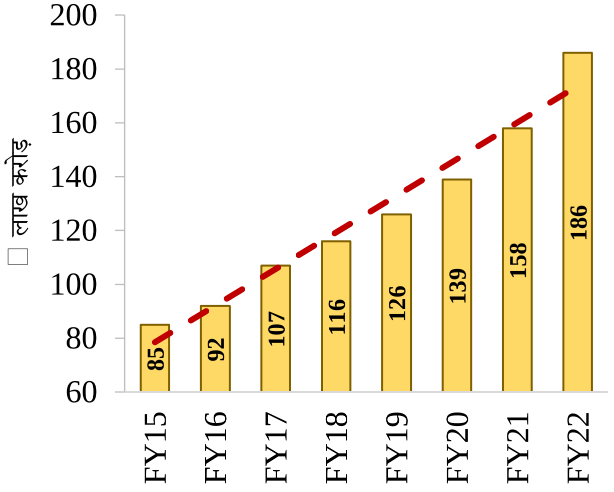

रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन

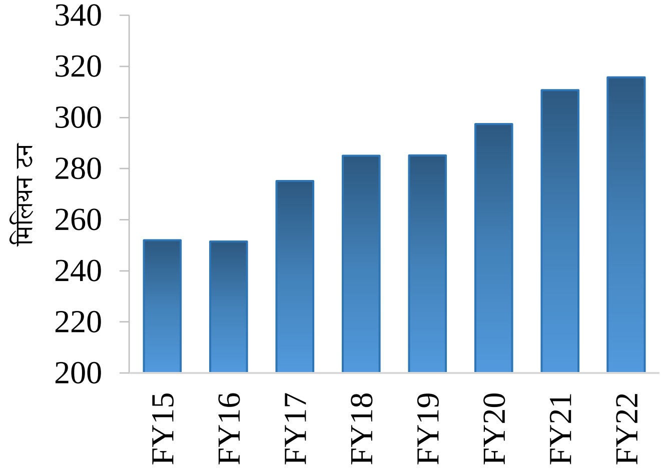

**एएनबी –आत्मनिर्भर भारत*

^आईआईएमआर – भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान

स्वास्थ्य

157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना

सिकल सैल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना

फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना

आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना

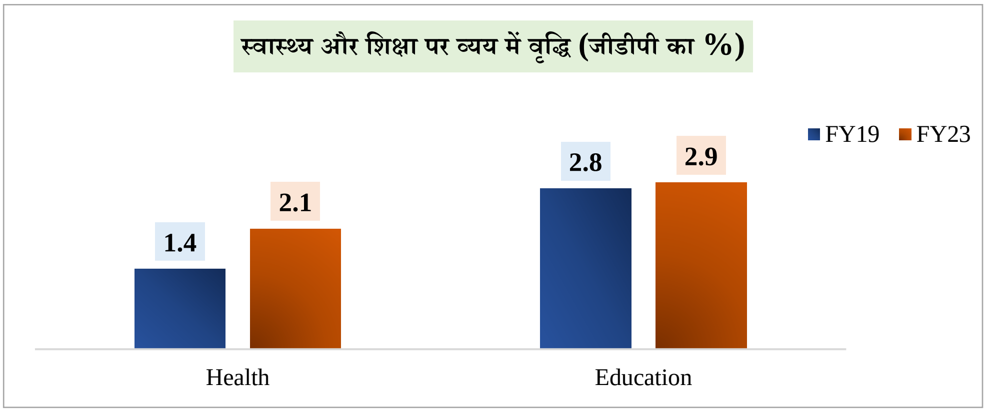

शिक्षा और कौशल

- ✓ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार
- ✓ **बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना**
- ✓ पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना

सभी के लिए सुविधाएं

ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन

पीएम – किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए □2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण

पीएमएसबीवाई* और पीएमजेजेवाई^ के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर

उपलब्धियां-समावेशी विकास

एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए

47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते

उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन

102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके

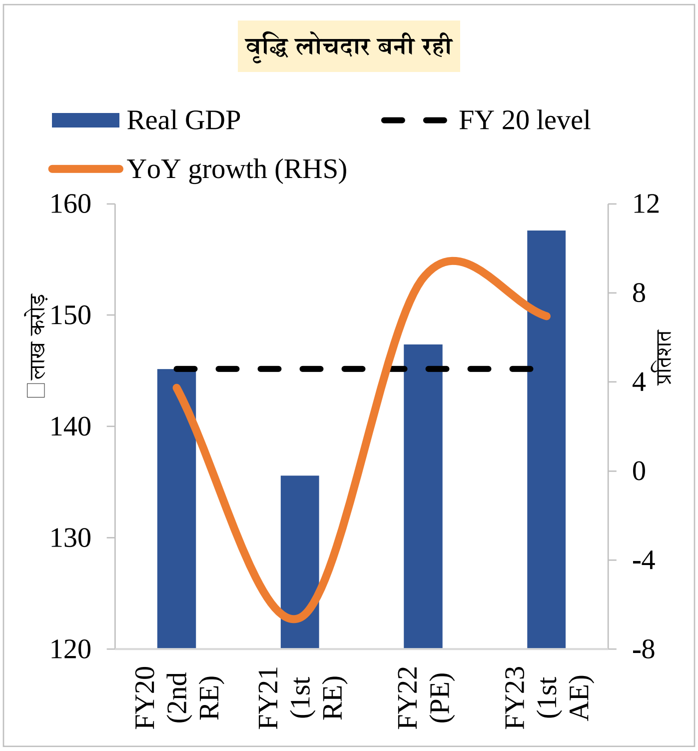

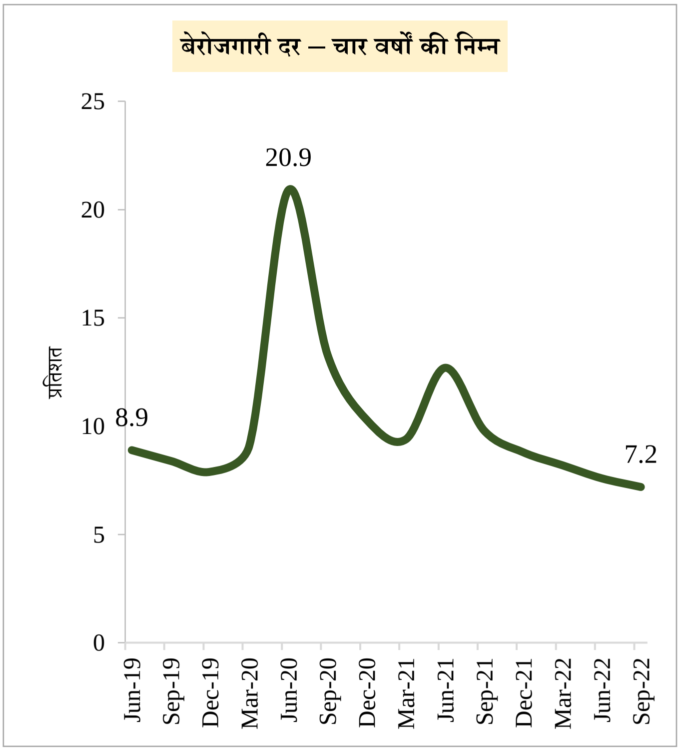

****पीएमएसबीवाई:** *प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना*

^पीएमजेजेवाई: *प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना*

अंतिम छोर तक पहुंचना

प्रधानमंत्री पीवीटीजी* विकास मिशन शुरू करना

कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता

740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना

प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत (श्री)^ की स्थापना

अवसंरचना और निवेश

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

गुणक प्रभाव →

विकास और रोजगार में वृद्धि

पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर □10 लाख करोड़ करना

अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना

रेलवे के लिए □2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय

पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं

यूआईडीएफ** की स्थापना द्वारा श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन

*पीवीटीजी:विशेष रूप से असुरक्षित आदिवासी समूह ^श्री: साझा अभिलेख निक्षेपागार
**यूआईडीएफ: शहरी अवसंरचना विकास निधि

क्षमता उभारना-आस्था आधारित सरकार

उपाय	संभावित परिणाम
भारत में एआई का निर्माण: तीन शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना करना	कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान
राष्ट्रीय डेटा शासन नीति *शुरू करना*	स्टार्ट-अप्स और अकादमियां द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाना
विवाद से विश्वास I-एमएसएमई के लिए *लचीला संविदा निष्पादन*	कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत
विवाद से विश्वास II-*सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम*	सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटान
ई-कोर्ट का चरण 3 शुरू करना	कारगर न्याय प्रशासन
व्यावसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के उपयोग हेतु ***एनटिटी डिजिलॉकर*** *की स्थापना करना*	व्यावसायिक पारितंत्र के साथ दस्तावेजों का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा करना सुसाध्य बनाना
5जी सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए ***100 प्रयोगशालाओं*** की स्थापना करना	रोजगार की संभावनाओं और व्यवसायों के अवसरों का उपयोग करना
प्रयोगशाला में निर्मित हीरा (एलजीडी) क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान	घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करना

हरित विकास

हरित ऋण कार्यक्रम

संभरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए* के तहत अधिसूचित किया जाना है।

पीएम- प्रणाम* की शुरूआत

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

500 नए 'अवशिष्ट से धन' संयंत्र

चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन# स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं।

संभरणीय पारितंत्र विकास

- तट रेखा के साथ-साथ मैन्ग्रूव पौधारोपण के लिए मिश्टी^ की शुरूआत
- आर्द्र भूमियों के ईष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन

अन्य पहलें

- किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केन्द्रों की स्थापना
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा
- ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा
- पुराने प्रदुषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन

अमृत पीढ़ी – युवा शक्ति

पीएमकेवीवाई 4.0 की शुरूआत

जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3डी मुद्रण, आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय

घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपरक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना है।

युनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन

युनिटी मॉल में ओडीओपी (एक जिला - एक उत्पाद), जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा।

** प्रणाम : पृथ्वी माता के पुनर्रुद्धार, इसके प्रति जागरुकता, इसके पोषण, और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम*
^ मिश्टी : तटीय वन्य-वासों और मूर्त आयों के लिए मैन्ग्रूव पहल
 # गोबरधन : गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-ऐग्रो रिसोर्सेज धन

वित्तीय क्षेत्र

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना

ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा

केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना

कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी।

महिला सम्मान बचत पत्र

महिलाओं के लिए ₹2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमाराशि को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया गया है

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम

₹2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार

अन्य पहलें

- जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहलें
- प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण-पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना

राजकोषीय प्रबंधन

राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण

- जिसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है
- राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबद्ध होंगे।

राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सहबद्ध) किया गया है।

राजकोषीय समेकन

वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ वृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा

राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार

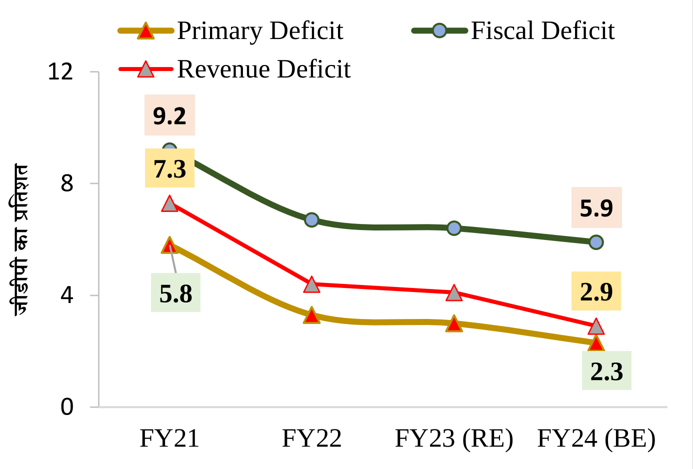

जीएसटी का मासिक राजस्व लगभग □1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा

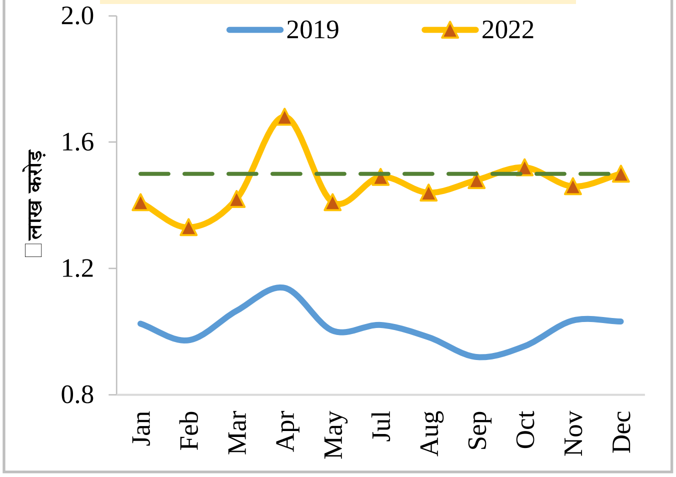

संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय

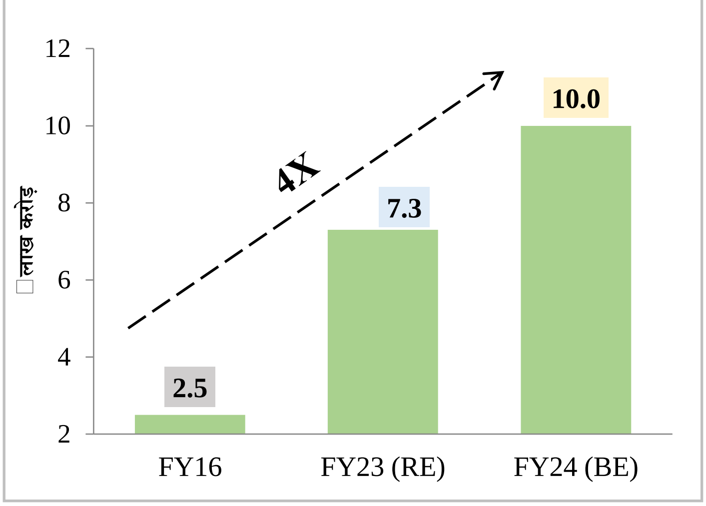

निम्न एनपीए के चलते बैंकों की सुधरती आस्ति गुणवत्ता

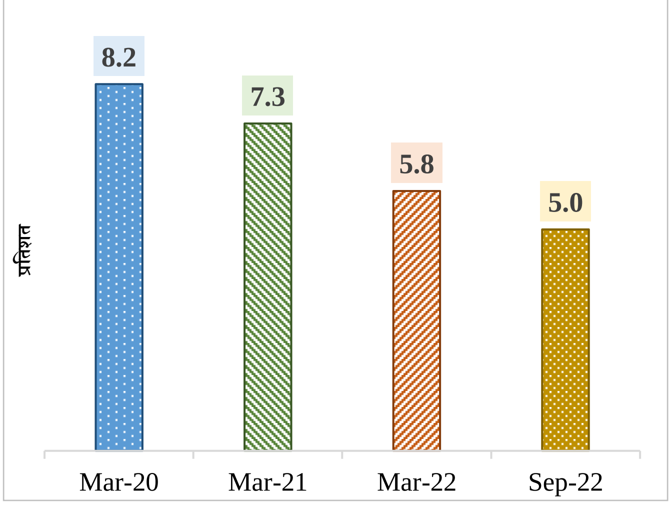

9 महीनों के आयातों को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार

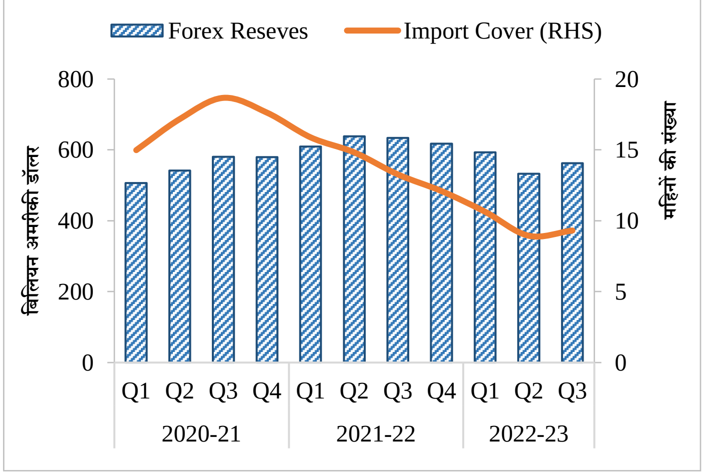

थोक मूल्यों से मेल खाते खुदरा मूल्य

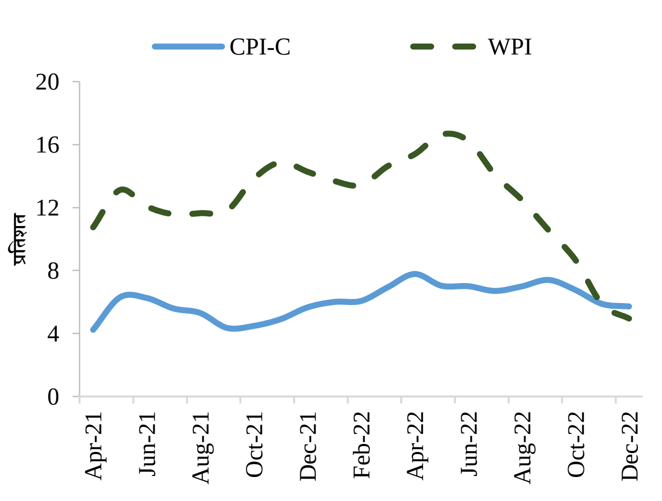

कर प्रस्ताव

अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ

उच्चतर निर्यात

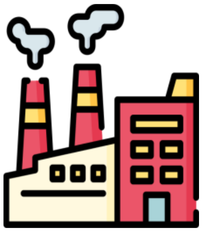

उच्चतर घरेलू विनिर्माण

अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन

हरित ऊर्जा और गतिशीलता

निम्नलिखित पर सीमाशुल्क में परिवर्तन	लाभ
लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात	पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए
मोबाइल कैमरा लैंसों के आयात	मूल्यवर्धन बढ़ाना
डीनैचर्ड इथाइल एल्कोहल	रसायन उद्योगों के लिए
श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट	अधिकाधिक समुद्री निर्यातों के लिए
प्रयोगशाला निर्मित हीरों के विनिर्माण के लिए बीज	निर्यात संवर्धन
कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमाशुल्क जारी रखना	एमएसएमई के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना
मिश्रित रबर, प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए	शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना

करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घण्टों के भीतर संसाधित किया गया

औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटकर 16 दिन रह गई

इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया

निजी आयकर को और सरल बनाना

नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को □5 लाख से बढ़ाकर □7 लाख किया गया

नई आयकर व्यवस्था

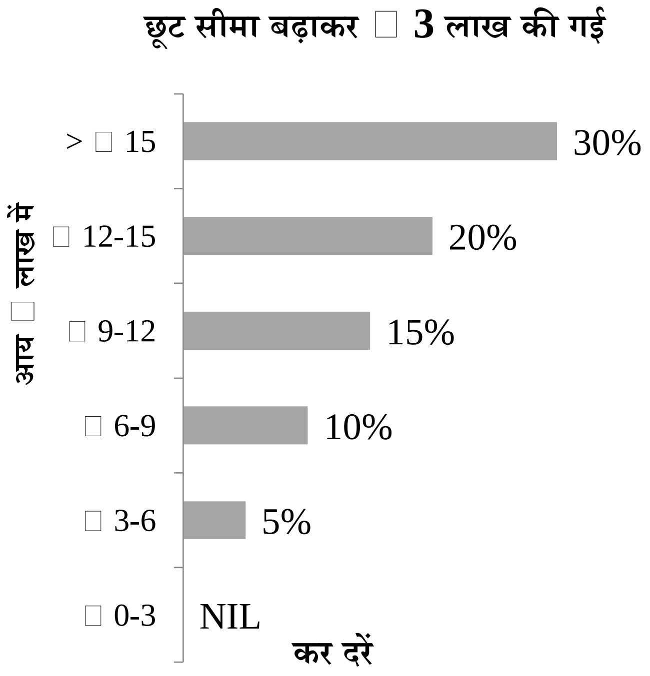

- नई व्यवस्था के तहत □5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% की गई
- वेतनभोगी और पेंशनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं
- गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर □25 लाख कर दिया गया है

उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण

एमएसएमई

- प्रकल्पित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यावसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना; 95% प्राप्तियां नकद रहित होंगी
- एमएसएमई को किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी

सहकारी समितियां

- 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाले नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ देना
- पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य □2 लाख की उच्चतर सीमा
- सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर टीडीएस के लिए □3 करोड़ की उच्चतर सीमा

स्टार्ट-अप्स

- स्टार्ट-अप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का एक वर्ष तक विस्तार
- स्टार्ट-अप्स की शेयरधारिता को निगमन के सात वर्ष से दस वर्ष में परिवर्तित करने पर हुई हानि को अग्रेनीत करने का लाभ

यौक्तिकीकरण

- केंद्र अथवा राज्य के संविधि द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों एवं आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आय कर से छूट
- 31 मार्च, 2025 तक आईएफएससी, जीआईएफटी सिटी को धनराशि को पुनःअंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि का विस्तार

रुपया कहां से आता है

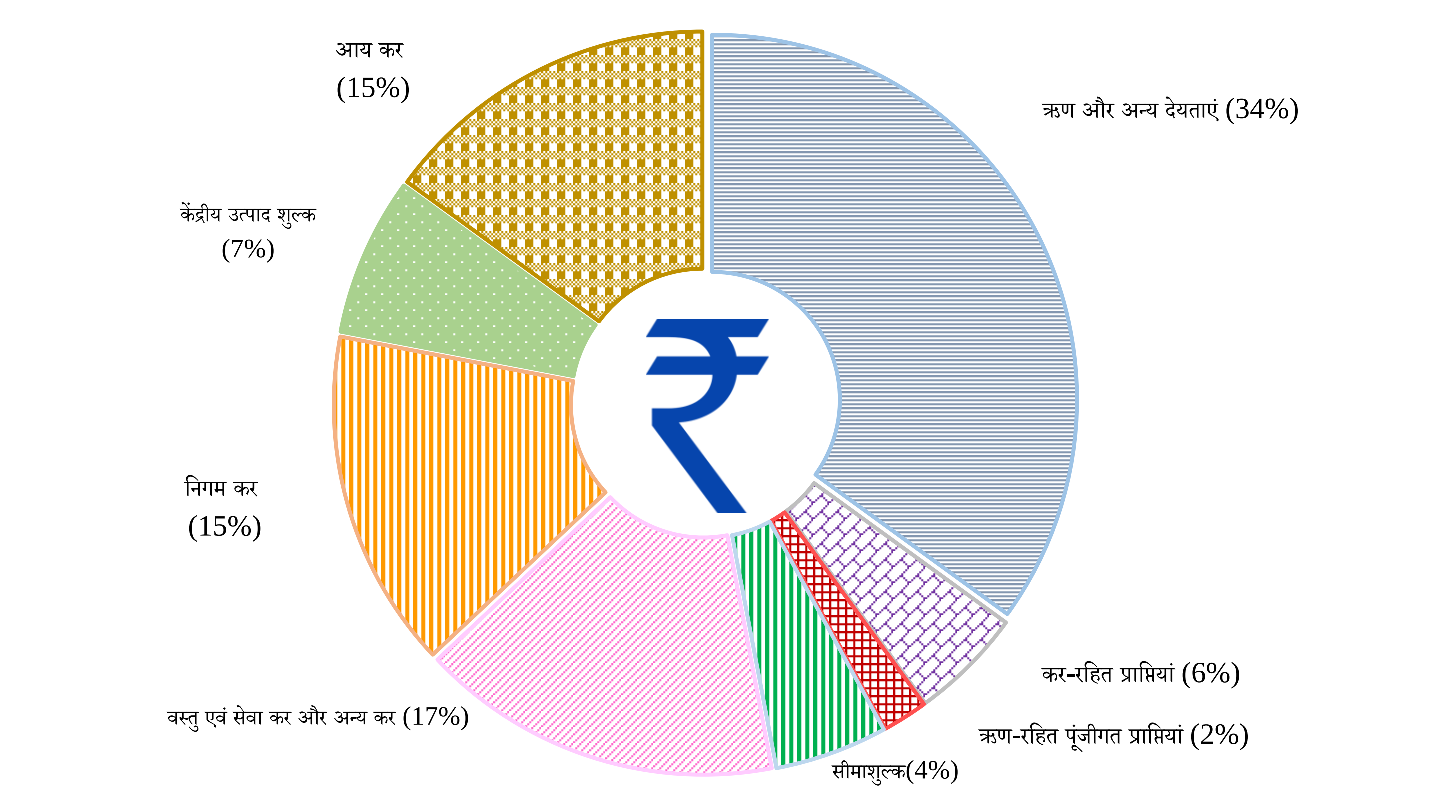

रुपया कहां जाता है

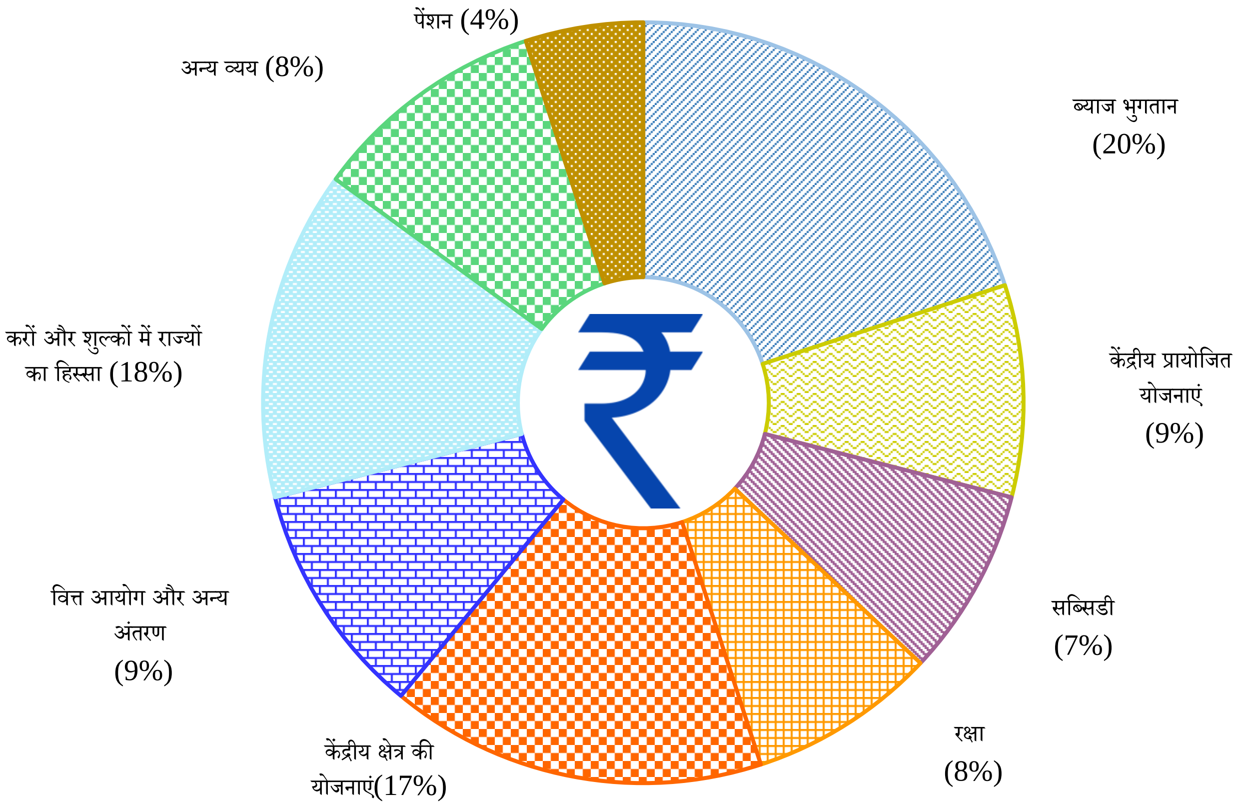

विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आबंटन

लाख करोड़ में

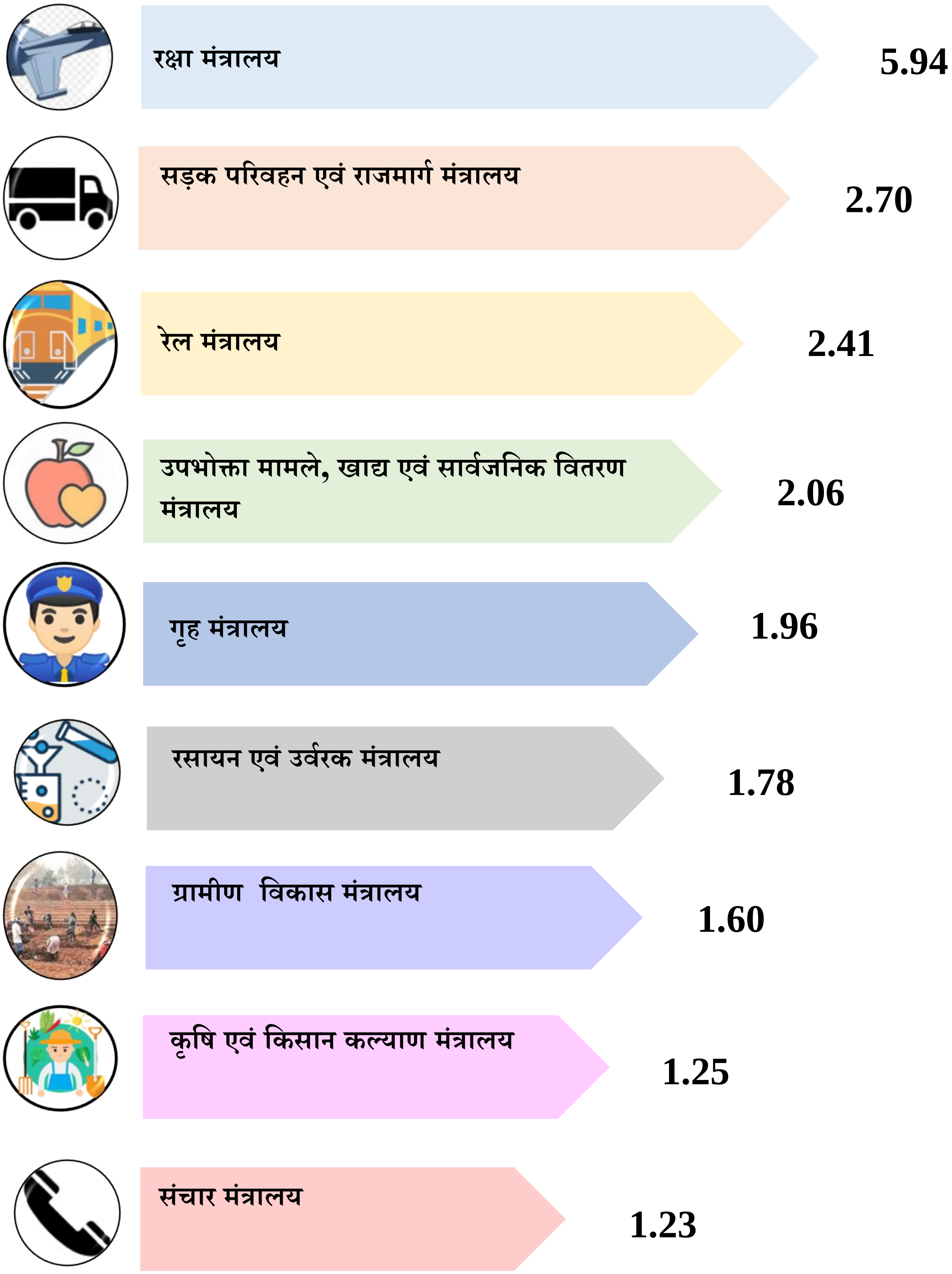

मुख्य योजनाओं के लिए आबंटन (₹ करोड़ में)

फार्मास्यूटिक्ल उद्योग का विकास

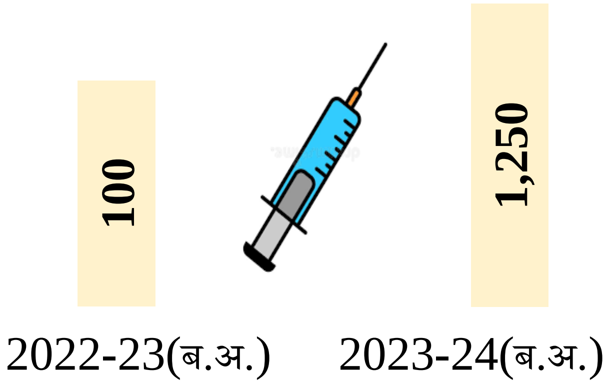

जल जीवन मिशन

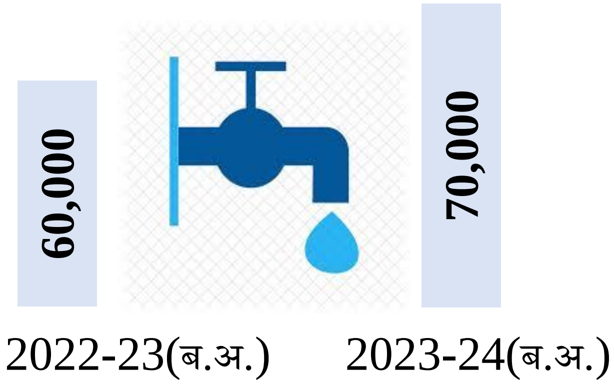

एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल

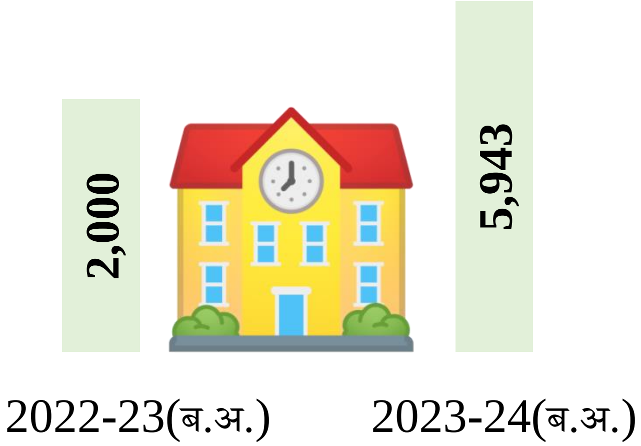

प्रधानमंत्री आवास योजना

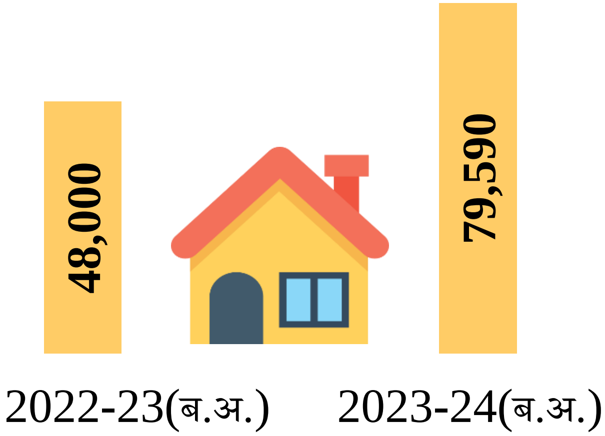

ईवी का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम)

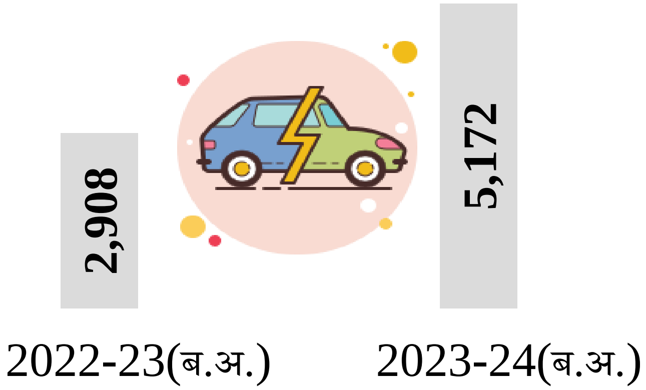

पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना

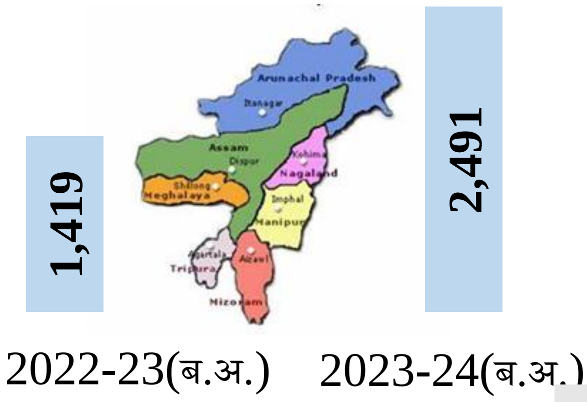

प्राप्तियां और व्यय (₹ लाख करोड़)